Availability of clozapine drug

3108. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Clozapine, a mental drug developed by Swiss Pharmaceutical Sandoz, is available in India; if so, at what price in the market;

(b) whether the equivalent of Clozapine drug is manufactured in India; if so, at what price;

(c) whether Government have compared it with Thorazine and its side effects; and

(d) whether any survey is done of the effects of various mental drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) Clozapine is neither manufactured nor marketed in India.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Government is not aware of any such survey.

प्रौद्योगिकी उन्नयन

3109. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1992 के 'स्टेटसमेन' में स्टेटकोला जी अपग्रडेशन ए मस्ट शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कोई उपाय किये है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और प्रौद्योगिकी उन्नयन के उपायों पर सरकार समय-समय पर ध्यान देती रही है । तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन देने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग और तकनीकी विकास महानिदेशालय (डीजीटीडी) ने अलग-अलग विषयों पर विभिन्न तकनीकी सलाहकार ग्रुप गठित किए है ताकि विद्यमान प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन किया जा सके और उन्नयन के उद्देश्य से अन्तराल का पता लगाया जा सके जिससे इसे और अधिक उपयुक्त और समकालीन बनाया जा सके ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सरकार के व्यय में योजनागत विकास के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जो पहली योजना (1951–56) में 20 करोड़ रुपए से बढ़कर छठी योजना में यह 3678 करोड़ रुपए हो गया है । वर्तमान में 1200 इन-हाउस अनुसंधान और विकास एकक वैद्य मान्यता प्राप्त है जिनमें से 350 रसायन और सम्बद्ध उद्योगों से है ।

मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास एककों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों और समर्थन के उपायों में आयात सुविधाएं आयकर में राहत, तीव्रतर मूल्यह्रास लाभ, राष्ट्रीय पुरस्कार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, जहां नयी प्रक्रियाएं अन्तर्ग्रस्त हों प्रपुंज औषधों के लिए मूल्य नियंत्रण आदेश से छूट आदि शामिल है ।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 46.5 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय से सात मुख्य परियोजनाएं आरम्भ की है ।

प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य से 1976 से तकनीकी विकास निधि योजना भी लागू है ।